राजगीर में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन

राष्ट्रीय खबर

संस्कृति मंत्रालय तथा डीम्ड यूनिवर्सिटी नव नालंदा महावीर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय "अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन" का आज उद्घाटन हुआ। बिहार के राजगीर इंटरनेशनल बौद्धिस्ट कांफ्रेंस में बौद्ध धर्म गुरू दलाई लामा तथा संस्कृति तथा पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।

- इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री एन के सिन्हा और नव नालंदा महावीर डीम्ड यूनिवर्सिटी के उप कुलपति श्री एम एल श्रीवास्तव भी मौजूद थे। इस अवसर पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा मंगला पथ का मंत्रोच्चारण भी किया गया।

- अपने उद्घाटन संबोधन के दौरान दलाई लामा ने कहा कि सभी धार्मिक परंपराओं की सच्चाई एक है जो कभी बदल नहीं सकती। इससे देश के साथ-साथ विश्व को भी प्यार और करुणा के माध्यम से शांति प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो बौद्ध धर्म का प्रमुख सूत्र है।
- उन्होंने कहा कि हमें न केवल बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ना चाहिए बल्कि इसका अपने जीवन में प्रयोग और अनुभव भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा की तरह करुणा भी मानव का एक बुनियादी स्वभाव है।
- उन्होंने भावनाओं पर जोर देते हुए कहा कि हमारे अंदर जो नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं उससे हम पीडित और बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें विपश्यना योग के माध्यम से मन को शुद्ध करना चाहिए।

एशिया में पहला एयरबस प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली में खुलेगा

राष्ट्रीय खबर

एयरबस नई दिल्ली स्थित एयरोसिटी में एक प्रशिक्षण केंद्र खोलेगा ताकि एयरबस पॉयलटों और इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया जा सके।

- इस संबंध में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू, एयरबस के कार्यकारी अधिकारी श्री टॉम एंडर्स और नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री की उपस्थिति में एक आयोजन किया गया।

- इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी. अशोक गजपति राजू ने कहा कि भारत में यात्री विमानों की मांग तेजी से बढ़ रही है जिसके लिए यह आवश्यक हो गया है कि कुशल पॉयलटों और इंजीनियरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र की भी आवश्यकता है ताकि कुशल श्रम शक्ति का विकास हो।
- एयरबस के कार्यकारी अधिकारी श्री टॉम एंडर्स ने कहा कि एयरबस का प्रशिक्षण केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जो इस बात का प्रतीक है कि भारत के साथ एयरबस की साझेदारी कितनी गहरी है।
- उल्लेखनीय है कि भारत में एयरबस के 250 से अधिक विमान संचालन में हैं और इंडियन एयरलाइन्स ने 570 से अधिक विमानों का आर्डर दिया है।

भारत के राष्ट्रपति करेंगे "भविष्य के विश्वविद्यालयों" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी कल (18 मार्च 2017) हरियाणा के सोनीपत में ओ पी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय में एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करेंगे ।

- इसका थीम विषय है "भविष्य के विश्वविद्यालय: ज्ञान, अभिनव और उत्तरदायित्व"।
- सम्मेलन बीसवीं सदी में भारतीय विश्वविद्यालयों के भविष्य की जांच करना चाहता है और इसमें तेरह विषयगत पैनल होंगे।
- इस अंतरराष्ट्रीय फोरम के विषयगत सत्र, अनुसंधान, ज्ञान निर्माण और प्रकाशन, नवाचार, विनियमन, नीति निर्माण, विश्वविद्यालयों के वित्तपोषण और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के आसपास के महत्वपूर्ण विषयों के लिए समर्पित हैं।

राष्ट्रीय खबर

एनटीपीसी ने 263.95 अरब यूनिट बिजली का सर्वाधिक उत्पादन किया

मौजूदा वर्ष में एनटीपीसी समूह ने अब तक का सबसे अधिक 263.95 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन किया है जो पिछले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 263.42 अरब यूनिट से अधिक है।

- इस तरह इस वर्ष एनटीपीसी ने पिछले वर्ष की तुलना में 4.71 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।
- एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 48,188 मेगा वॉट है, जिसमें 19 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 10 सौर ऊर्जा आधारित और 1 पन बिजली संयंत्र शामिल हैं।
- इनके अलावा 9 सहायक /संयुक्त उपक्रम वाले बिजली घर भी मौजूद हैं।
- एनटीपीसी की पहली कोयला खान हजारीबाग में पकरी-बड़वाडीह दिसंबर, 2016 में चालू हो गई थी।
- कंपनी की पहली पवन ऊर्जा परियोजना गुजरात में शुरू हुई थी।
- एनटीपीसी ने अभी हाल में देश के सबसे बड़े 100 केडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सोलर पीवी संयंत्र का उद्घाटन किया जिसे केरल में लगाया गया है।

राष्ट्रीय खबर

पांच साल की मिशन अवधि के लिए तेलंगाना को अटल मिशन निवेश की मंजूरी

कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल मिशन (अमृत) की केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत 2019-20 तक तेलंगाना के 12 मिशन शहरों के बुनियादी शहरी ढांचे में सुधार के लिए 1,673 करोड़ रूपये खर्च किये जाएंगे। यह मिशन का अंतिम वर्ष होगा।

- केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने अटल मिशन के तहत अगले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान (2017-2020) 703 करोड़ रूपये की मंजूरी दी है। मिशन का कुल निवेश 1,673 करोड़ रूपये है।
- 2015-16 के लिए 415 करोड़ रूपये और 2016-17 के लिए 555 करोड़ रूपये के व्यय को संबंधित वर्षों के लिए राज्य वार्षिक योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित

किया गया था, जिसे पहले शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया।

- शहरी विकास मंत्रालय ने पांच साल के मिशन के लिए कुल 832 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की, जो कुल खर्चे का लगभग आधा हिस्सा है और इसे तेलंगाना के 12 मिशन शहरों पर खर्च किया जाना है।
- 2017-2020 के लिए 703 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें मिशन शहरों में 560 करोड़ रूपये जलापूर्ति परियोजनाओं पर, 126 करोड़ रूपये सीवरेज नेटवर्क के विस्तार तथा 17 करोड़ रूपये पार्को और हरित क्षेत्रों के निर्माण पर खर्च होंगे।
- इसमें से 424.26 करोड़ रूपये वारंगल में जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए खर्च किये जाएंगे।

अटल मिशन (अमृत) के तहत उत्तर प्रदेश में बुनियादी, शहरी संरचना के लिए 11,421 करोड़ रुपये का निवेश

केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत उत्तर प्रदेश में 11,421 करोड़ रुपये की कुल धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अंतर्गत वर्ष 2019-20 तक 1 लाख से अधिक आबादी वाले 61 शहरों और नगरों में बुनियादी शहरी संरचना में सुधार किया जाएगा।

- इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लिए अमृत कार्य योजना को स्वीकृति दी है जो 2017 – 2020 के दौरान चलेगी। इसकी कुल लागत 4,239 करोड़ रुपये वार्षिक कार्ययोजना के तहत यानी 2015-16 और 2016-17 के संदर्भ में है। अटल मिशन के अंतर्गत यह सबसे बड़ा निवेश है।
- तमिलनाडु के लिए वर्ष 2017 – 2020 के दौरान 4,154 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है। इस तरह 33 शहरों में कुल मिशन निवेश 11,237 करोड़ रुपये का है।
- महाराष्ट्र में 44 मिशन शहरों और नगरों के लिए 2015-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 6,759 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- इसी तरह हरियाणा में 20 मिशन शहरों और नगरों के लिए 2017-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 2,544 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ में 9 मिशन शहरों और नगरों के लिए 2015-20 के दौरान बुनियादी शहरी संरचना में सुधार के लिए 2,192 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

भारतीय नदियों के तलछट प्रबंधन पर सम्मेलन संपन्न

सरकार जल्दी ही एक नदी तलछट प्रबंधन नीति का विकास करेगी।

- यह बात केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन श्री नरेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली में भारतीय नदियों में तलछट प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा।
- श्री कुमार ने कहा कि पूर्व में कई समितियां गठित की गई जिन्होने तलछट की समस्या पर अध्ययन किया और नदियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त उपाय सुझाये।

- उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन इस दिशा में एक और आगे बढ़ता हुआ कदम होगा और विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप एक व्यापक नीति विकसित होगी।
- श्री कुमार ने कहा कि तलछट प्रबंधन की एक पद्धति का निर्माण करना आवश्यक है जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो और व्यावहारिक, तकनीकी, तथा आर्थिक रूप से भी संभव हो।
- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्वास के मंत्रालय में संयुक्त सचिव (पीपी) श्री संजय कुंडू ने अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को संदर्भित किया जहां उन्होंने नदी की देश में तलछट प्रबंधन नीति की जरूरत को रेखांकित किया।
- उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन में उपस्थित विशेषज्ञ उपयुक्त सिफारिशें सुझाएंगे जो सरकार द्वारा राष्ट्रीय सिल्ट प्रबंधन नीति को तैयार करने में मदद करेगा।